(b) if so, the action of Government thereon

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government is aware of the new vistas of international collaboration open-ing up in the held of education.

गुजरात में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

1579. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :** क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में प्राथमिक शिक्षा हेतु एक नया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना को उन क्षेत्रों में भी शुरू किया जा रहा है जहां पूर्ण साक्षरता अभियान सफल रहे हैं और जिसके परिणामस्वरूप प्राथमिक शिक्षा की मांग बढ़ी है।

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) गुजरात में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत आज की स्थिति के अनुसार जिलेवार परिणाम क्या रहे हैं ; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य को जिलेवार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) जी हां। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन. पी. ई.) और इसकी कारंवाई योजना (पी. ओ. ए.) को ध्यान में रखते हुए विकेन्द्रीकृत आयोजना और पृथक-पृथक लक्ष्य निर्धारण की कार्य योजना को लागू करने के लिए "जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.)" नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। कुल मिला कर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा का विस्तृत रूप में पुनर्गठन करना है न कि स्कीमों का थोड़ा-थोड़ा कार्यान्वयन करना। कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों के चयन का मानदंड निम्न प्रकार है :

(क) शैक्षिक रूप से पिछड़े ऐसे जिले जहां महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है ; और

(ख) ऐसे जिले जहां संपूर्ण साक्षरता अभियान सफल रहे हैं और जिसके कारण प्रारंभिक शिक्षा के लिए मांग बढ़ी है।

वर्तमान समय में कार्यक्रम को 7 राज्यों—असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिल नाडु, केरल और मध्य प्रदेश के 42 जिलों में कार्यान्वित किया गया है।

(घ) और (ङ) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) से संबंधित दिशा-निर्देश गुजरात सरकार को उपलब्ध करा दिए गए हैं।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन

1580. **श्री सत्य प्रकाश मालविया :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 12 अगस्त, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2551 के दिये गये उत्तर देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम 1915 में संशोधन करने से संबंधित मामले की वर्तमान अवस्था क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 के संशोधन प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के लिए गठित की गई समिति ने अभी अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

Opening Study Centres of IGNOU in Foreign Countries

1581. SHRI SANJAY DALMIA : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether the Study Centres of the Indira Gandhi National Open University have been opened in foreign countries;

(b) if so, the names of the countries where these Centres have been opened;

(c) whether there is a scheme to open more study Centres in future; and

(d) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DPETT. OF CULTURE] (KUMARI SEJLA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) IGNOU has a target of setting up 20 more centres during 1994-95 within the country.

मध्य प्रदेश में विदिशा के विजय मन्दिर में संग्रहालय स्थापित किया जाना

1582. **श्री राघवजी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित विजय मन्दिर परिसर में प्राप्त मूर्तियों एवं शिलालेखों को सुरक्षित रखने तथा आम नागरिकों के दर्शनार्थ कोई संग्रहालय बनाने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त परिसर में स्थित बावड़ी की सफाई का कार्य कराया है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो यह कब तक कराये जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का विचार है कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित विजय मन्दिर स्थल से प्राप्त मूर्तियों और शिलालेखों को सुरक्षित रखने तथा आम नागरिकों के दर्शनार्थ रखने के लिए मूर्ति-शैड बनाया जाए । मूर्ति-शैड की दीवारें पहले ही खड़ी की जा चुकी हैं तथा छत बनाने का कार्य चल रहा है ।

(ग) उपर्युक्त परिसर में स्थित तालाब की सफाई का कार्य वर्ष 1992 में आरंभ किया गया था । कूड़ा-कचरा और गारा-मिट्टी को हटा दिया गया है । इस समय तालाब की सीढ़ियों पर पानी मौजूद है । जैसे ही पानी घटेगा, अगला मरम्मत कार्य शुरू कर दिया जाएगा ।

National Youfh Policy

1583. SHRI GOVINDRAO ADIK : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether there is a proposal under consideration of Government for formulating a comprehensive national youth policy for the development of the youth of the country;

(b) whether this policy document wil! also focus on same powers to be given to (he youth like representation on some bodies etc.;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS) (SHRI MUKUL WASNIK) : (a) to (d) Government of India has already formulated a National Youth Policy which was laid before the Parliament in the winter session of 1988- The National Youth Policy is comprehensive and deals with a wide variety of programmes of Youth Welfare and development, and seeks to provide the youth with new opportunities to participate in nation-building activities. It also aims at providing the youth with maximum access to education which includes professional and vocational training.

Making Distance Education More Credible

1584. SHRI GOVINDRAO ADIK : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) what steps Government are taking to make distance education more credible with emphasis on quality;

(b) what are the guidelines for support to State Open Universities as recommended by a panel in its report submitted to the Distance Education Council and referred to in the news item in the "Hindustan Times*' of 28th June, 1994 under the caption "Efforts on to make distance education more credible".